B.ed 1st year Paper-C2 - Unit-2

उच्च शिक्षा की समस्याएँ

माध्यमिक शिक्षा की समाप्ति के उपरांत उच्च शिक्षा प्रारम्भ होती है। उच्च शिक्षा महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों, विविध शिक्षा संस्थानों आदि में प्रदान की जाती है। आधुनिक भारतीय उच्च शिक्षा की आधारशिला सन् 1857 ई० में रखी गई थी। सन् 1857 ई० में वुड के घोषणापत्र में भारत में विश्वविद्यालय खोलने की सिफारिश की गई थी। जिसके परिणाम स्वरूप सन् 1857 ई० में कोलकत्ता, बम्बई, और मद्रास में तीन विश्व-विद्यालय खोले गए थे स्वतंत्रता प्राप्ति तक भारत में 20 विश्वविद्यालय थी स्वतंत्रता के उपरांत उच्च स्तरों की शिक्षा का विस्तार काफी तेजी से हुआ एक अनुमान के अनुसार इस समय भारत वर्ष में लगभग 600 से अधिक विश्वविद्यालय तथा मानक विश्व-विद्यालय या उच्च शिक्षा संस्थान है। जिससे लगभग 30 हजार महाविद्यालय संबंधित है तथा इनमें लगभग 2 crore 40 lakh छात्र अध्ययन कर रहे है।

विश्वविद्यालय के प्रकार

कोठारी आयोग के अनुसार

" विश्वविद्यालय वह संस्थान है ~~जहाँ~~ जहाँ पर सदा अपने-अपने योगदान द्वारा सत्य की खोज करते है तथा

अपनी शैक्षिक उन्नति के द्वारा व्यक्तित्व का विकास करते है।"

भारतीय विश्वविद्यालयों को तीन आधारों पर विभाजित किया जा सकता है :—

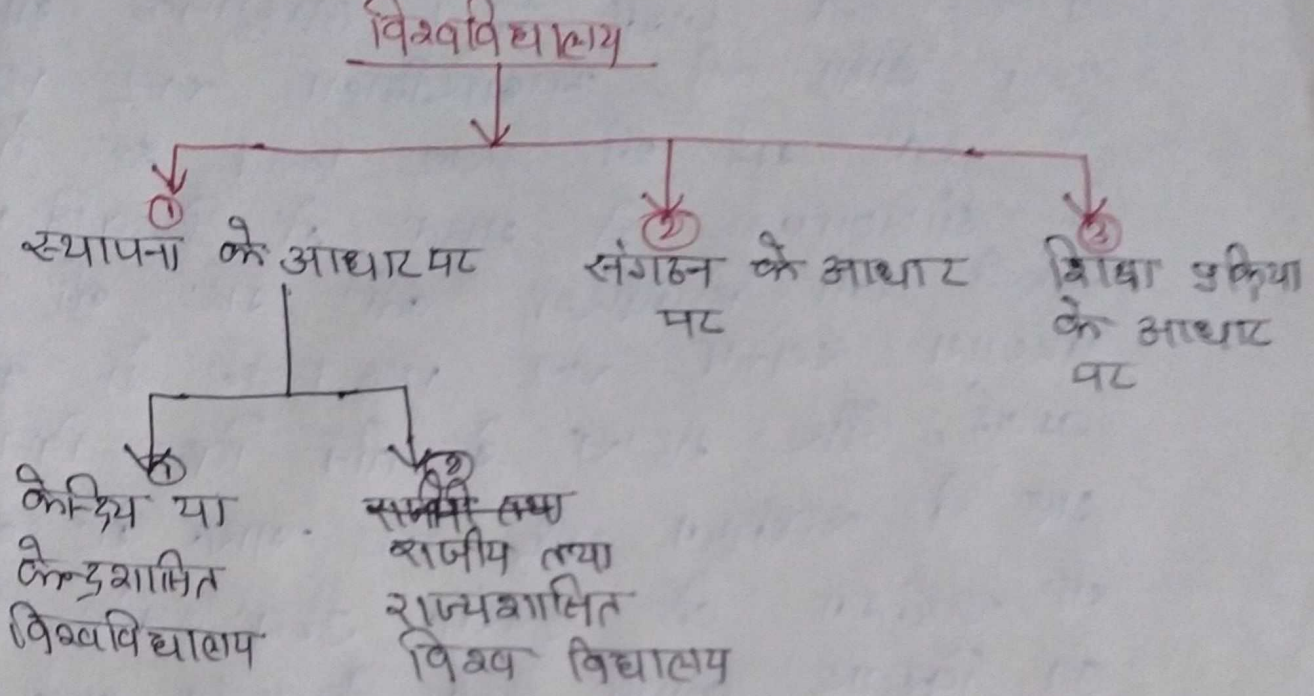

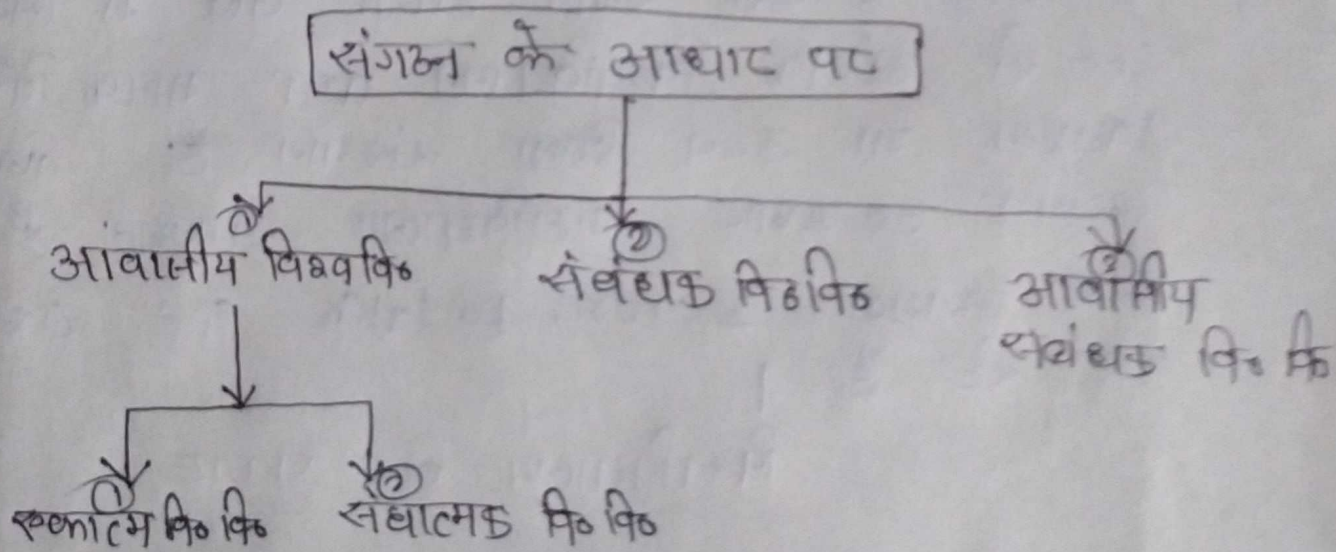

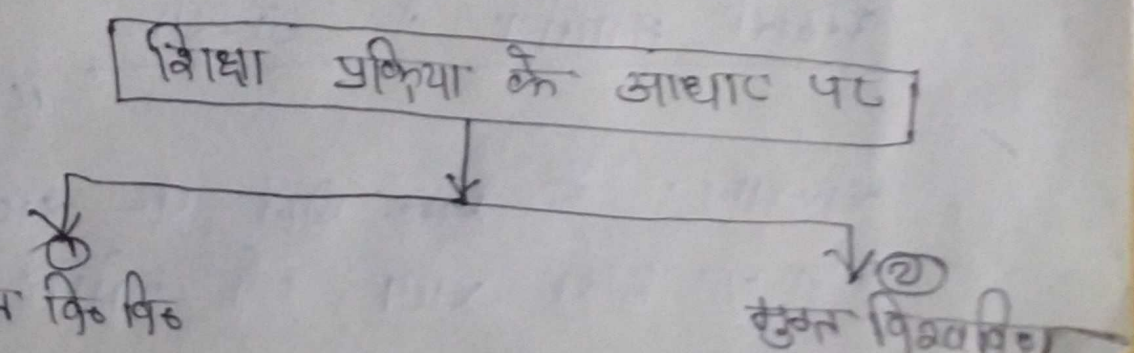

उच्च शिक्षा की समस्याएँ :-

उच्च शिक्षा के संबंध में विशेष बात यह है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय उसका संख्यात्मक विकास अत्यंत त्वरित गति से हुआ है साथ ही इसकी विशेष बात यह है कि इसका विकास आदि से अंत तक अनियोजित रहा है परिणामतः उच्च शिक्षा का स्तर गिरता गया और छात्रों में ज्ञानार्जन की अभिलाषा नष्ट होती गई जो उच्च शिक्षा के लिए बहुत बड़ी समस्या है।

हमारे देश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विद्यमान समस्याएँ और समाधान निम्नलिखित है :-

1) उद्देश्यहीनता की समस्या :-

आजकल छात्रों में उच्च शिक्षा के प्रति उद्देश्यहीनता पाई जाती है। निरुद्देश्य हमें निराशा की ओर ले जाती है। आज के अधिकतर स्नातकों में ये लक्षण स्पष्ट प्रतीत होते है विश्वविद्यालयी शिक्षा आयोग में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विश्वविद्यालय शिक्षा देश के नागरिकों को बौद्धिक, नैतिक एवं अध्यात्मिक प्रगति तथा राष्ट्रीय समृद्धि की ओर अग्रसर ~~कर~~ कर सकती है।

हमारी उच्च शिक्षा की उद्देश्यहीनता एक सर्वविदित तथ्य है समय बदल गया है देश की परिस्थितियाँ बदल गई है पर खेद का विषय यह है कि उच्च शिक्षा का अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए निर्धारित किया गया था यह स्वतंत्रता प्राप्ति के वर्षों बाद भी अपने पुरातन

रूप में उच्चशिक्षा पर अपना अखण्ड साम्राज्य स्थापित किए हुए है।

समाधान ⇒ (i) देश की वर्तमान परिस्थितियों नागरिकताओं की आकांक्षाओं के अनुरूप उच्च शिक्षा के उद्देश्य निश्चित किए जाने चाहिए और इसके लिए शिक्षा आयोग (1964 से 1966) द्वारा सुझाए गए निम्नलिखित उद्देश्यों का अनुपालन किया जाना चाहिए।

ii) नवीन ज्ञान की खोज और विकास करना सत्य की खोज के लिए उत्साह और निर्भिकता से संलग्न होना।

iii) प्राचीन ज्ञान और विश्वासों की नवीन आवश्यकताओं पर खोजों के विषय में व्यवस्था करना।

iv) जीवन के सभी क्षेत्रों में उचित प्रकार का नेतृत्व प्रदान करना।

अनुशासन हीनता की समस्याएँ ः

शिक्षा की सबसे विकराल समस्या छात्रों में अनुशासनहीनता ही है। छात्रों द्वारा शिक्षण संस्थानों के नियमों का पालन न करना छात्र अनुशासन हीनता की श्रेणी में आता है, परन्तु इसके अंतर्गत व्यवहार मानदण्डों और शासन के नियमों व कानून को न मानना ही सम्मिलित होता है। कोठारी आयोग के अनुसार इस समस्या के प्रमुख कारण निम्नलिखित है :—

i) अनिश्चित भविष्य की आशंका ।
ii) छात्रों और अध्यापकों में पारस्परिक संबंध का अभाव ।
iii) शिक्षा संस्थाओं की विशालतम संख्या ।
iv) शिक्षण और सीखने की अपर्याप्त सुविधाएँ
v) अध्यापकों की परस्पर राजनीति ।

समाधान :-

इस समस्या के समाधान हेतु निम्नलिखित प्रयास किए जाने चाहिए :-

i) उच्च शिक्षा में मुक्त प्रवेश प्रणाली के स्थान पर चयनात्मक प्रणाली का प्रयोग किया जाय और मेधावी एवं योग्य छात्रों को प्रवेश दिया जाए अध्यापक शिक्षार्थी का अनुपात 1:20 हो जिससे इन दोनों के बीच निकट के संबंध स्थापित हो सके ।

ii) कुलपतियों एवं प्रचार्यों की नियुक्ति उनकी शैक्षिक योग्यता के साथ-साथ प्रशासनिक कुशलता के आधार पर की जाए ।

iii) उच्च शिक्षण संस्थाओं को साधन सम्पन्न किया जाए अध्यापक को जवाबदेही निश्चित की जाए ।

iv) छात्रवृत्तियों की व्यवस्था योग्यता और आर्थिक स्थिति के आधार पर की जाए ।

v) परीक्षाओं में होनेवाले पक्षपात को रोका जाए निजी ट्यूशन पर प्रतिबंध लगाया जाए ।

शिक्षित बेरोजगारी समस्या :-

शिक्षित बेरोजगारी से तात्पर्य है शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार न मिलना अथवा अपनी बौद्धिक योग्यता एवं कार्य कुशलता के ~~निचे का~~ नीचे का रोजगार मिलना। प्राय: इसका मुख्य कारण शिक्षा का रोजगार उन्मुख न होना मानते है परन्तु वास्तव में इसका मुख्य कारण है उच्च शिक्षा का आवश्यकता से विस्तार देश की बेरोजगारी बढ़ाने में उनकी आर्थिक नीति तथा बड़े उद्योगों का प्रोत्साहन।

समाधान :-

इस समस्या के समाधान हेतु उच्च शिक्षा के अनावश्यक विस्तार को रोका जाना चाहिए और भारी उद्योगो के स्थान पर लघु उद्योग को प्रोत्साहन देना चाहिए।

अव्यय और अवरोध की समस्या :-

उच्च स्तर पर अव्यय एवं अवरोध का पहला कारण यह है कि इस स्तर पर मुक्त प्रवेश प्रणाली है और जहाँ चयनात्मक प्रवेश प्रणाली है वहाँ जाति, धर्म और लिंग आदि के आधार पर आरक्षण है, इसरा कारण है कि 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर वोट का अधिकार, छात्र संघो का निर्माण उनमें राजनीतिक दलो का हस्तक्षेप और छात्रो की राजनीति है।

समाधान :-
इस समस्या के समाधान हेतु उच्च शिक्षा में चयनात्मक प्रवेश प्रणाली को ईमानदारी से लागू करने हेतु था एवं आरक्षण समाप्त किया जाए अथवा उनके लिए न्यूनतम योग्ताएँ निर्धारित कि जाए। विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में छात्र संघों के कारण हंगामें की प्रवृति विकसित हुई है इनके निर्माण पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।

Page-1

Q बिहार में शिक्षा का ऐतिहासिक विकास ।

⇒ एक समय बिहार शिक्षा के सर्वप्रथम केन्द्रों में गिना जाता था । नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय प्राचीन बिहार के गौरवशाली अध्ययन केन्द्र थे । सन् 1917 में खुलने वाला पटना विश्वविद्यालय काफी हद तक अपनी प्रतिष्ठा कायम रखने में सफल रहा किंतु स्वतंत्रता पश्चात शैक्षणिक स्थानों में हो रहा राजनीति तथा आकर्मण्यता करने से शिक्षा की स्तर पर गिरावट आया हाल के दिनों में उच्च शिक्षा की स्थिती सुधरने लगी है । प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा में भारी गिरावट आई है । हाल ही में पटना में एक भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान तथा हाजीपुर में केन्द्रिय प्लास्टिक इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट तथा केन्द्रिय औषधि शिक्षा एवं शोध संस्था खोला गया है जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था के लिए एक अच्छा संकेत है ।

सर्व शिक्षा अभियान

सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत वर्ष (2000-01) में हुई । जिसका उद्देश्य सार्वभौमिक सुलभता एवं प्रतिधारण प्रारंभिक शिक्षा में बालक-बालिका एवं सामाजिक श्रेणी के अन्तरों को दूर करने तथा अधिगम की गुणवत्ता से सुधार हेतु नए स्कूल खोला जाना एवं वैकल्पिक स्कूलों की सुविधाएँ प्राप्त करना

अध्यापकों की व्यवस्था करना, प्रसाधन कक्ष एवं पेय की सुविधा प्रदान करना आदि शामिल है।

सर्व शिक्षा अभियान जिला आधारित एक विशिष्ट विकेन्द्रिय योजना है इसके माध्यम से प्रारम्भिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करने की योजना है। इस अभियान के अंतर्गत राज्यों की भागीदारी से (6-14 वर्ष) की आयु के बच्चों को 2010 तक प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था।